or assisted by HUDCO and other housing development agencies like NBCC; and

(b) the amount of investment involved and the number of tenements so far constructed during the past three years, under these schemes?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BHISHMA NARAIN SINGH): (a) and (b). State-wise Projects assisted, investment involved and tenements constructed through financial assistance by Housing and Urban Development Corporation are given in Annexure.

National Buildings Construction Corporation have not implemented or assisted any rural housing project.

Statement

Statement and Year-wise Details on Rural Housing Projects Financed By Hudco

State	1977-78			1978-79			1979-80		
	No. of Projects	Loan amount (Rs. in crores)	Dwelling sanctioned;	No. of Project	Loan amount (Rs. in crores)	Dwelling sanctioned	No. of Projects	Loan amount (Rs. in crores)	Dwelling Sanctioned
Andhra Pradesh	1	0·03	249	—	—	..	7	3 83	23580
Gujarat	3	0·44	5827	3	1·13	6800	6	1·55	13790
Karnataka	1	5·00	50000	..	..	..	4	4·25	42500
Kerala	1	5·00	25000	2	3·50	20000	1	1·00	5000
Madhya Pradesh	..	..	..	2	0·08	400	..	..	..
Punjab	1	0·78	3946	..	..	..	1	0 93	4637
Tamil Nadu	..	..	..	..	..	..	10	3 06	16491
West Bengal	..	..	..	1	0·04	200	..	..	..
	7	11 25	85022	8	4·75	27400	29	14·62	105998

समर्थन मूल्य पर धान की वसूली

75. **श्री जय राम वर्मा :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि समर्थन मूल्य पर धान की वसूली अभी तक उचित प्रकार से शुरु नहीं की गई है जिसके परिणामस्वरुप मंडियों में धान के मूल्य कम हो गये हैं और छोटे तथा गरीब किसानों को जिन्हें अपनी आवश्यकतायें पूरी करने के लिए धान बेचना पड़ता है, हानि हो रही है ;

(ख) यदि हां तो अब तक धान की वसूली के लिये उचित व्यवस्था न करने के क्या कारण हैं और इसके लिये व्यवस्था कब की जायेगी और प्रत्येक राज्य में इसकी वसूली के लिये लगी हुई एजेन्सियों के नाम क्या है ;

(ग) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि धान के लिये घोषित 105 रुपये प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य से किसान संतुष्ट नहीं हैं जिसके परिणाम स्वरुप वे उत्पादन बढ़ाने के लिये निरुत्साहित हुए हैं ; और

(घ) यदि हां तो इस मामल में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख). जी नहीं । हालांकि वसूली मौसम के प्रारम्भ में कुछेक राज्यों में कुछेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब उचित प्रबन्ध कर दिये गए हैं। अद्यतन सूचनानुसार वसूली कार्य पूरे वेग से चल रहे हैं। सरकारी एजेन्सियों ने 14-11-1980 तक 25.78 लाख मीटरी टन धान वसूल कर ली हैं जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 14.71 लाख मीटरी टन की वसूली की गई थी अर्थात् वसूली में लगभग 75 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। एक विवरण संलग्न है, जिसमें इस समय धान की वसूली करने में लगी एजेन्सियों का ब्यौरा दिया गया है ।

(ग) और (घ). सरकार ने केवल न्यूनतम समर्थन मूल्य ही निर्धारित किया है और किसान अपना उत्पाद बाजार में अत्याधिक उपलब्ध मूल्य पर बेचने में स्वतन्त्र हैं। कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के बाद तथा राज्य सरकारों के साथ परामर्श करने के बाद ही समर्थन मूल्य निर्धारित किए गए हैं। कुल मिलाकर सरकार द्वारा निर्धारित किए गए समर्थन मूल्यों के बारे में प्रतिक्रिया अनुकूल रही है।

विवरण

राज्य	ऐजेन्सी
1. आन्ध्र प्रदेश	भारतीय खाद्य निगम, राज्य सिविल सप्लाई कारपोरेशन
2. हरियाणा	भारतीय खाद्य निगम, 'हफेड'
3. हिमाचल प्रदेश	भारतीय खाद्य निगम
4. जम्मू तथा काश्मीर	राज्य सरकार
5. महाराष्ट्र	राज्य सरकार
6. पंजाब	भारतीय खाद्य निगम, राज्य सरकार, 'पं0 सप0', 'मार्कफेड'
7. तमिलनाडु	भारतीय खाद्य निगम राज्य सिविल सप्लाई कारपोरेशन, कोआप0
8. उत्तर प्रदेश	राज्य सरकार, राज्य सिविल सप्लाई कार-पोरेशन, कोआप0
9. दिल्ली	भारतीय खाद्य निगम
10. पांडिचेरी	भारतीय खाद्य निगम ।

समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों द्वारा की गई विदेशों की यात्रायें

76. श्री दया राम शाक्य : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) समाज कल्याण विभाग के सचिव और अधिकारियों ने वर्ष 1978-1979 और 1980 के दौरान कितनी विदेश की यात्राएं की हैं उन अधिकारियों के नाम क्या हैं प्रत्येक ने कितनी यात्रायें की हैं और उन में से प्रत्येक ने राज्यों में विभिन्न केन्द्रों की कितनी यात्राएं की हैं; और

(ख) उन की विदेशों की यात्राओं पर वर्ष-वार कितना व्यय हुआ है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) और (ख). एक विवरण, जिस में उप सचिव तथा उस से ऊंचे दर्जों के अधिकारियों के सम्बन्ध में जानकारी दी गई है, संलग्न है।